टाटा ग्रुप में आया बड़ा भूचाल

- चंद्रा की दोबारा नियुक्ति पर नोएल टाटा ने उठाए सवाल
- बोर्ड वोटिंग को बताया अवैध शर्तों के उल्लंघन का आरोप

नवभारत न्यूज नेटवर्क.

नयी दिल्ली, 20 सितंबर. टाटा ग्रुप में एक बार फिर बोर्डरूम का घमासान दुनिया के सामने आ गया है जहां टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा ने टाटा संस की बोर्ड बैठक में एन. चंद्रशेखरन से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर हुई वोटिंग प्रक्रिया को सीधे तौर पर 'अवैध और शून्य' घोषित कर दिया है.

नोएल टाटा ने आरोप लगाया है कि यह पूरी प्रक्रिया टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच लंबे समय से चले आ रहे कॉरपोरेट गवर्नेंस नियमों का उल्लंघन करती है और यह स्पष्ट रूप से 'विश्वासघात' का मामला है. इस कदम ने टाटा ग्रुप की टॉप लीडरशिप में प्रशासनिक और कानूनी संतुलन पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं. नोएल टाटा का तर्क है कि टाटा संस के होल्डिंग फ्रेमवर्क में 66 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स के नामित निदेशकों की सहमति और स्थापित प्रक्रियाओं की अनदेखी करके लिया गया कोई भी निर्णय वैधानिक रूप से अमान्य है. इस विवाद के सार्वजनिक होने से कॉरपोरेट गलियारों में हड़कंप मच गया है, और बाजार की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि टाटा संस का बोर्ड इस गंभीर चुनौती का जवाब कैसे देता है. टाटा संस पर उठे सवाल : टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने टाटा संस

बोर्ड मीटिंग की वैधता पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और दूसरे प्रस्तावों पर वोटिंग कुछ शर्तों के साथ हुई थी, जिनका बाद में पालन नहीं किया गया.

टाटा संस को करना होगा नियमों का पालन : यह बैठक ऐसे समय में हुई जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा संस की उस अर्जी को ठुकरा दिया था, जिसमें उसने अपनी 'कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने और 'अपर-लेयर एनबीएफसी' पर लागू होने वाले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर रहने की मांग की थी. आरबीआई के इस फैसले का मतलब है कि टाटा संस को लागू नियमों का पालन करना होगा, जिसमें लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है.

नियुक्ति का प्रस्ताव 'शुरुआत से ही अमान्य' था. उन्होंने मांग की कि कंपनी मीटिंग में हुई घटनाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से सुधार जारी करे. यह चिट्ठी चंद्रा की दोबारा नियुक्ति को लेकर चल रही सार्वजनिक बहस के बीच आई है. टाटा संस के बोर्ड ने 4-1 के बहुमत से उनकी वापसी के पक्ष में वोट किया था. नोएल टाटा की चिट्ठी: मेरा मानना है कि जिस मामले (चेयरमैन की दोबारा नियुक्ति) पर वोटिंग हुई और जिस प्रस्ताव को पास हुआ बताया जा रहा है, वह शुरू से ही अमान्य और बेकार है. इसकी कोई कानूनी अहमियत, असर या प्रभाव नहीं है.

> टाटा संस के कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय को लिखे और सभी डायरेक्टर्स को भेजे गए एक कड़े शब्दों वाले पत्र में, टाटा ने कहा कि चेयरमैन की दोबारा चंद्रशेखरन के सामने आने वाले समय में कई बड़ी चुनौतिया है. इनमें एयर इंडिया कर पाटा, जमुआर लैंड रोवर की कमजोर स्थिति और टाटा संस की लिस्टिंग जैसे कई बड़े मुद्दे हैं.दूसरी तरफ टाटा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर कारोबार में तेजी से निवेश कर रहा है. कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में एप्पल और टेस्ला जैसे ग्राहक जुड़े हैं.

त्योहार में नहीं बढ़ेंगे एफएमसीजी के दाम

- चीनी, खाद्य तेल, कॉफी और कोको की लागत बढ़ी
- जून तिमाही में चुनिंदा उत्पाद 2 से 5% महंगे हुए

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 20 सितम्बर त्योहारी सीजन में ग्राहकों को एफएमसीजी उत्पादों की कीमतों पर फिलहाल राहत मिल सकती है. चीनी, खाद्य तेल, कॉफी, कोको और पैकेजिंग सामग्री जैसे कच्चे माल की लागत बढ़ने के बावजूद ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियां तुरंत कीमतें बढ़ाने से बच रही हैं.

कंपनियों का फोकस इस समय दाम बढ़ाने के बजाय बिक्री की मात्रा बढ़ाकर कारोबार को गति देने पर है. उद्योग के अनुसार, त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद है और कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी कर इस मांग को प्रभावित नहीं करना चाहतीं.

कई कंपनियां बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा पहले ही ग्राहकों तक पहुंचा चुकी हैं. जून तिमाही में चुनिंदा उत्पादों की कीमतों में करीब 2 से 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई थी. ऐसे में लगातार दूसरी बार कीमत बढ़ाने से कंपनियों को मांग कमजोर होने का खतरा है.

महिलाओं की रोजगार भागीदारी में बड़ा अंतर

- 10 में 8 महिलाएं कामकाजी, कहीं पांच में एक भी नहीं
- हमीरपुर में महिला श्रम भागीदारी 80.9%, पूर्वी दिल्ली में 18.9%
- सूरत समग्र श्रम भागीदारी में आगे, दरभंगा सबसे निचले स्तर पर
- पूर्वी दिल्ली में बेरोजगारी 8.3%, दिल्ली में एनईईटी दर 44.3%

नवभारत न्यूज नेटवर्क.

नयी दिल्ली, 20 सितंबर महिलाओं की रोजगार में भागीदारी की तस्वीर जिला बदलते ही पूरी तरह बदल जाती है. कहीं 10 में से आठ महिलाएं श्रम बाजार का हिस्सा हैं, तो कहीं यह आंकड़ा पांच में एक से भी कम है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने पूरे देश में पहली जिला स्तर पर श्रम बाजार का सर्वेक्षण जारी किया जिससे ये चौंकाने - वाले आंकड़े सामने आए हैं. संशोधित - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के तहत जिला - स्तर पर चार श्रेणियों, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार-जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), बेरोजगारी दर (यूआर) और 15-29 वर्ष के वे युवा जो रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण किसी में शामिल नहीं हैं (एनईईटी) का डाटा - जुटाया गया है. एनएसओ के इन आंकड़ों के अनुसार राज्यों के महिला आबादी के - लिहाज से 10 सबसे बड़े जिलों में एक - हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में महिला श्रम बल भागीदारी 80.9% रही जो देश में - सबसे अधिक है. वहीं पूर्वी दिल्ली में यह आंकड़ा सिर्फ 18.9% रहा. जम्मू-कश्मीर के बडगाम में यह 71.4%, ओडिशा के मयूरभंज में 71.8 फीसदी और छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 69 फीसदी रही.

समग्र श्रम बाजार की तस्वीर में गुजरात का सूरत प्रमुख जिलों में सबसे आगे रहा. यहां कुल श्रम भागीदारी 68.6% और डब्ल्यूपीआर 67.8% दर्ज किया गया. इसके बाद बिहार का अररिया और तमिलनाडु का सलेम रहे, जबकि दोनों मानकों पर बिहार का दरभंगा सबसे निचले स्तर पर रहा. दक्षिण-पश्चिम दिल्ली ने 46.7 फीसदी श्रम बल दर और 45.2 फीसदी कार्यबल जनसंख्या अनुपात में है.

सीए के काम में मददगार हो सकता है एआई

- उसकी जगह नहीं ले सकता: आईसीएआई अध्यक्ष
- समय बचा रहा एआई, अंतिम निर्णय सीए ही लेंगे

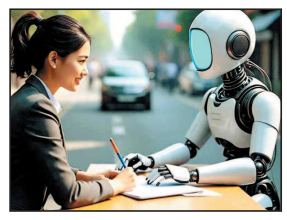

नवभारत न्यूज नेटवर्क

कोच्चि, 20 सितंबर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार डी. का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम में मददगार हो सकती है, लेकिन उसकी जगह कभी नहीं ले सकती.

प्रसन्ना ने यहां शनिवार शाम कहा कि एआई डाटा तैयार करने में काफी सहायक है, इससे ऑडिटिंग के काम में लगने वाला समय काफी कम हुआ है, लेकिन यह एक सीए की भूमिका को समाप्त नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि नैतिकता बनाए रखने के लिहाज से भी यह जरूरी है.

उन्होंने कहा, 'एआई कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रोजगार का संकट नहीं बन सकता, ऐसा कभी नहीं होगा.चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं.' एआई के इस्तेमाल के प्रति सावधानी बरतने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि एआई से जो नतीजे सामने आते हैं, उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता. नैतिकता सीए के खून में होती है. उन्होंने कहा, 'जहां तक एआई का सवाल है, हमें देखना होगा कि नैतिकता के पैमाने पर यह सही है या नहीं.'

उन्होंने कहा कि एआई से ऑडिटिंग के काम में समय की बचत हो रही है. यह अकाउंटेंसी के काम में मददगार साबित हुआ है, जहां एक ही डाटा की कई अलग-अलग एंट्री हो सकती है. लेकिन ऑडिट के काम में एआई सिर्फ डाटा दे सकता है, आंकलन और राय देने के काम में पेशेवर सीए की जरूरत बनी रहेगी. प्रसन्ना ने कहा, 'कुल मिलाकर एआई से प्रदर्शन में सुधार होगा. यह मददगार है. बिना एआई को अपनाये आज के समय में सीए पहले की तरह अपनी प्रैक्टिस जारी नहीं रख सकते. इसलिए, हम इसका स्वागत करते हैं. उपाध्यक्ष मंगेश किनरे ने कहा कि एआई आने के बाद से सीए की मांग वास्तव में बढ़ गयी है. उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और बढ़ते कारोबार के साथ सीए की मांग भी बढ़ रही है.

> आईसीएआई अध्यक्ष ने कहा कि संस्थान चार्टर्ड अकाउंटेंट को एआई के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन साथ ही अंतिम निर्णय खुद अपने विवेक और अनुभव के आधार पर लेने के लिए प्रोत्साहित करता है.उन्होंने कहा कि सीए के लिए आईसीएआई ने एआई में सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए हैं. समें उन्हें यह बताया जाता है कि एआई का इस्तेमाल कैसे करना है और वे अपने कार्यालयों में खुद का एआई टूल कैसे बना सकते हैं. अब तक 55 हजार सीए को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है.

मारुति का हरित वाहनों पर बड़ा दांव

नई दिल्ली. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएस आईएल) ने चालू वित्त वर्ष में सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलाकर 10 लाख हरित वाहन बेचने का लक्ष्य रखा है. कंपनी को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और सीएनजी वाहनों में स्वचालित ट्रांसमिशन की शुरुआत से इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है. हरित वाहन ऐसे पर्यावरण अनुकूल वाहन हैं जो पारंपरिक पेट्रोल या डीजल की तुलना में बहुत कम या शून्य प्रदूषण फैलाते हैं. कार बाजार की अग्रणी कंपनी ने अपने 'ऑटो ग्रीन मिशन' के तहत शुक्रवार को अपने लोकप्रिय मॉडल स्विफ्ट, डिजायर और बलेनो के स्वचालित एस-सीएनजी संस्करण पेश किए,

रिकॉर्ड से फिसला विदेशी मुद्रा भंडार

- रिकॉर्ड ऊंचाई से 4.924 अरब डॉलर घटा भंडार
- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 2.372 अरब डॉलर की कमी
- सोने के भंडार का मूल्य भी 2.591 अरब डॉलर घटा

नवभारत न्यूज नेटवर्क

मुंबई, 20 सितंबर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, 11 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई है.

यह भंडार 4.924 अरब अमेरिकी डॉलर घटकर 780.782 अरब अमेरिकी डॉलर पर आ गया. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और स्वर्ण भंडार में कमी इस गिरावट का मुख्य कारण रही. आरबीआई ने यह जानकारी जारी की. इससे पहले, पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था. तब यह रिकॉर्ड 44.903 अरब अमेरिकी डॉलर की भारी वृद्धि के साथ 785.706 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था. ताजा गिरावट ने इस रिकॉर्ड ऊंचाई से भंडार को नीचे ला दिया है.

ये परिसंपत्तियां 2.372 अरब अमेरिकी डॉलर घटकर 645.796 अरब अमेरिकी डॉलर रह गईं. केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है. डॉलर के संदर्भ में व्यक्त की जाने वाली इन परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव शामिल होता है.

अगले हफ्ते 6 दिन बंद रहेंगे बैंक

नई दिल्ली. अगर अगले सप्ताह बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं तो तारीख देखकर शाखा जाएं. 21 से 27 सितंबर 2026 के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक छह दिन बंद रहेंगे. हालांकि, इन सभी छुट्टियों का असर पूरे देश में एक साथ नहीं होगा. क्षेत्रीय त्योहारों के कारण अलग-अलग शहरों में बैंक शाखाओं का अवकाश रहेगा. इसके अलावा 26 को चौथा शनिवार और 27 को रविवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे.

पेट्रोल पंप पर 2000 से ज्यादा का होता रहेगा यूपीआई भुगतान

इंडियन ऑयल ने किया खंडन, एमपी में डिजिटल भुगतान पर कोई रोक नहीं

- 23 सितंबर को 'नो-यूपीआई डे' मनाने की बात भी गलत
- पेट्रोल पंपों पर स्वीकार होगा डिजिटल भुगतान

नवभारत न्यूज

भोपाल 20 सितम्बर. मध्यप्रदेश के पेट्रोल पंपों पर 2 हजार रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर रोक लगाने और 23 सितंबर को 'नो-यूपीआई डे' मनाने की वायरल खबर को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फर्जी और भ्रामक बताया है.

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर यूपीआई भुगतान को लेकर ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है. ग्राहक पहले की तरह डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकेंगे.

सोशल मीडिया पर वायरल संदेश में दावा किया जा रहा था कि मर्चेंट शुल्क के विरोध में पेट्रोल पंप संचालक 2 हजार रुपए से अधिक का यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे. संदेश में 23 सितंबर को इंदौर में सांकेतिक विरोध के तौर पर 'नो-यूपीआई डे' मनाने की बात भी कही गई थी. आईओसीएल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से इस दावे का खंडन करते हुए इसे अफवाह बताया.

कंपनी के अनुसार, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से हड़ताल या 'नो-यूपीआई डे' को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. एसोसिएशन के प्रतिनिधि संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क में हैं. आईओसीएल ने यह भी कहा कि पेट्रोल पंप संचालक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में लगातार सहयोग कर रहे हैं और ग्राहकों के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा जारी रहेगी.इस तरह 2 हजार रुपए की सीमा और 23 सितंबर को यूपीआई बंद रखने से जुड़ा वायरल संदेश तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है.

समाचार विशेष

क्या बसपा परिवार में ही तलाशेगी उत्तराधिकारी

- भतीजे आकाश के बाद चर्चा में भतीजी दीपिका आनंद का नाम

नवभारत न्यूज कनेक्ट

लखनऊ, 20 सितंबर. मायावती के सामने इस वक्त सिर्फ बसपा को अगले चुनाव में मजबूत करने की चुनौती ही नहीं है, उनके सामने यह भी तय करने का मौका है कि उनकी राजनीतिक विरासत आगे कैसे चलेगी.

कांशीराम के बाद उन्होंने अपने दम पर पार्टी को खड़ा किया और यूपी की राजनीति में मजबूत ताकत बनीं. लेकिन, अब बड़ा सवाल है कि उनके बाद बसपा की कमान कौन संभालेगा और क्या वह व्यक्ति परिवार से ही होगा? जिस तरह उत्तराधिकारी को लेकर मायावती खुद कंफ्यूजन में दिख रही हैं, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी दुविधा पैदा हो रही है. वह कभी अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ाती हैं और फिर कुछ समय बाद उनसे दूरी बना लेती हैं. आकाश को अब पार्टी से अलग किया जा चुका है. मायावती ने अपनी भतीजी दीपिका आनंद का नाम आगे किया है. सवाल है कि क्या बसपा का भविष्य सिर्फ परिवार के भीतर ही तलाशा जाएगा? मायावती परिवारवाद से दूरी की बात जरूर करती हैं, लेकिन उत्तराधिकारी वह परिवार में ही ढूंढती दिखती हैं. अगर मायावती को परिवार से बाहर ऐसा कोई कार्यकर्ता दिखाई ही नहीं देता, जिसे वह भविष्य में पार्टी की कमान सौंप सकें तो यह उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल है. इतने लंबे वक्त में अगर पार्टी में दूसरी कतार का नेतृत्व तैयार नहीं हो पाया तो इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ उत्तराधिकारी की नहीं है.

कांशीराम की कसौटी

मायावती के लिए शायद यह सही वक्त है कि वह उत्तराधिकारी चुनने की पूरी प्रक्रिया को परिवार से बाहर भी देखें. कांशीराम ने मायावती की नेतृत्व क्षमता देखकर उन्हें आगे बढ़ाया था. मायावती भी अगर अपने आसपास किसी ऐसे कार्यकर्ता को देखती हैं, तो उसे आगे बढ़ाने में हिचक क्यों? यह इसलिए भी अहम है क्योंकि बसपा को कांशीराम ने सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक ताकत में बदला और मायावती ने इसे यूपी की सत्ता तक पहुंचाया. ऐसे में अगर अगली पीढ़ी का नेतृत्व तय करने में परिवार ही सबसे अहम कसौटी बन जाए तो यह कांशीराम की बनाई राजनीतिक संस्कृति से अलग रास्ता होगा. परिवार से कोई योग्य नेता हो सकता है, लेकिन सिर्फ परिवार में होना ही योग्यता का विकल्प नहीं हो सकता.

तटरक्षक बल ने अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया

इस अभियान में 100 से अधिक तटीय स्थानों पर 25,079 स्वयंसेवकों ने भाग लिया

नवभारत कनेक्ट

नई दिल्ली, 20 सितंबर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत तथा भारत सरकार के प्रमुख अभियानों 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'स्वच्छता ही सेवा' के अनुरूप, भारतीय तटरक्षक बल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निकट समन्वय से आज, 19 सितंबर को सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2026 का आयोजन किया.

यह आयोजन 'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर 5.0' के समापन के रूप में आयोजित किया गया. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 12 से 19 सितंबर 2026 तक चलाए गए इस सप्ताहव्यापी समुद्र संरक्षण अभियान का उद्देश्य नागरिकों की निरंतर भागीदारी के माध्यम से समुद्री प्रदूषण से निपटना था. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाले इस अभियान का भारत में समन्वय भारतीय तटरक्षक बल द्वारा वर्ष 2006 से किया जा रहा है. अभियान में नागरिक और सैन्य क्षेत्र के बीच मजबूत समन्वय देखने को मिला. इस अभियान में 100 से अधिक तटीय स्थानों पर 25,079 स्वयंसेवकों ने भाग लिया. सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप 30,554 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे और समुद्री मलबे को एकत्र कर निस्तारित किया गया, जिससे भारत के समुद्र तटों पर पर्यावरणीय खतरों को कम करने में मदद मिली. अभियान में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, शैक्षणिक संस्थानों, वैज्ञानिक संगठनों, स्थानीय मछुआरा समुदायों और नागरिक समाज संगठनों ने सक्रिय भागीदारी की.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बढ़ाया सियासी पारा

- हैदराबाद के निजाम को बताया बेहतरीन शासक

नवभारत न्यूज कनेक्ट

हैदराबाद, 20 सितंबर. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के एक बयान ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने हैदराबाद के निजाम के शासन और राज्य के विकास में उनके योगदान की तारीफ करते हुए उन्हें बेहतरीन शासकों में से एक बताया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि निज़ाम ने जमीन से मिलने वाले लगान की आय का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे और संस्थानों के निर्माण में लगाया, जिनमें से कई आज भी तेलंगाना की पहचान और विकास की रीढ़ बने हुए हैं. एक कार्यक्रम में बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि निजाम एक महान सम्राट और शासक थे, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया. उन्होंने कहा कि निजाम ने जमीन के लगान के महत्व को सही तरीके से समझा और अपने शासनकाल में इससे होने वाली आय का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वजह से निज़ाम को बेहतरीन शासकों में से एक माना जाता है. उन्होंने कहा, निजाम सागर प्रोजेक्ट, निजाम शुगर फैक्ट्री, निजाम कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्डिंग, हाई कोर्ट, सिटी कॉलेज और उस्मानिया हॉस्पिटल ये सभी प्रोजेक्ट आज भी चल रहे हैं.

रेवंत रेड्डी का यह रुख कई लोगों के लिए हैरानी भरा माना जा रहा है, क्योंकि टीडीपी प्रमुख निजाम के मुखर आलोचक रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान पर अलग-अलग राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है. एक तरफ मुख्यमंत्री ने उन संस्थानों और परियोजनाओं के निर्माण के लिए निज़ाम की तारीफ की है, जो आज भी हैदराबाद और तेलंगाना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

आलोचकों को दिया जवाब

रेवंत रेड्डी का यह बयान उन लोगों के लिए जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो लगातार निज़ाम के शासन की आलोचना करते रहे हैं. निजाम 1947 में भारत की आजादी से पहले हैदराबाद राज्य के शासक थे. आजादी के बाद हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय से पहले तक निज़ाम का शासन था. मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में निजाम के योगदान का बचाव करते हुए कहा कि लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए भी उन्हें याद रखना चाहिए.

जवाबदेही उत्तरी छोटानागपुर : झामुमो की राजनीति में आई शून्यता!

क्या कल्पना सोरेन की बढ़ेगी जिम्मेदारी?

नवभारत न्यूज नेटवर्क

रांची, 20 सितंबर. पहले झारखंड टाइगर के रूप में चर्चित राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का असामयिक निधन और अब राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार का दिल के दौरा पड़ने से निधन हो जाने से राज्य ने जहां एक जानदार और तेजतर्रार नेता खो दिया.

वहीं यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी एक बड़ी क्षति है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और हेमंत मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उत्तरी छोटानागपुर की राजनीति में शून्यता की स्थिति पैदा हो गई है. अगर मंत्री योगेंद्र प्रसाद और पूर्व मंत्री मथुरा महतो ये दो नाम जरूर उत्तरी छोटानागपुर के झामुमो नेता के रूप में हैं, लेकिन जरूरत के समय पार्टी के लिए हर

मोर्चे ओर लड़ने-भिड़ने वाले ग्रासरूट नेता के रूप में सुदिव्य कुमार सोनू की कमी पार्टी को जरूर महसूस होगी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय झामुमो की राजनीति में आई इस शून्यता को स्वीकार भी करते हैं. वह कहते हैं कि उत्तरी छोटानागपुर में दूर-दूर तक कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता है जो सभी मायनों में सुदिव्य कुमार सोनू की कमी को निकट भविष्य में पूरा कर सके. सुदिव्य कुमार सोनू के असामयिक निधन से आई राजनीतिक शून्यता खास कर उत्तरी छोटानागपुर में कौन भरेगा, इस जगह को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

> झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू के जाने के बाद जो वैक्यूम पैदा हुआ है, वह सामान्य राजनीतिक रिक्तता नहीं है. उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली में कई ऐसी खूबियां थीं, जिन्हें पार्टी एक तरह से अपनी 'इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी' मानती थी. किसी भी सवाल का तत्काल और तार्किक जवाब देना, विषय की गहराई को समझना और उस पर निर्णय लेने की क्षमता उनकी खासियत थी. सुदिव्य कुमार सोनू हर विषय की बारीकी को समझते थे और निर्णय लेने की क्षमता रखते थे. वह जमीन से जुड़े हुए नेता थे और आम लोगों के साथ उनका सीधा जुड़ाव था. यही वजह थी कि बहुत कम समय में उन्होंने लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता और ख्याति हासिल कर ली.